कमांकः–डी0बी0एस0एल0एन0 (एस0बी0एम0–जी0)/2025–26.....967 to 1006
कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी,
विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन, हि0 प्र0।

प्रेषित,

समस्त पंचायत सचिव,
विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन, हि0 प्र0।

दिनांकः– सोलन 24 मई, 2025

विषयः– पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिये 15 वें वित्तायोग से सम्बन्धित अनुदानों के हस्तान्तरण और यूजर चार्जिज के संग्रह पर मन्त्रीमण्डल के निर्णयों का कार्यान्वयन, परिचालन निर्देश और एस0ओ0पी0 जारी करने बारे।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय पर सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज), हि0 प्र0 के कार्यालय पत्र संख्या पी0सी0एच0–एफ0(1)–1/2025 दिनांक 15 मई, 2025 द्वारा अवगत करवाया गया है कि 15 वें वित्तायोग के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिये ग्राम पंचायतों के लिये अनुदान निर्धारित किये गये हैं। हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 11 ग्राम पंचायत के कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। विशेष रूप से इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत अधिनियम की अनुसूची–1 में निर्दिष्ट कार्यों के साथ–साथ ग्राम पंचायत के अन्य कार्य उत्तरदायित्वों का पालन करेगी जिसमें स्वच्छता, संरक्षण और उपद्रवों की रोकथाम से सम्बन्धित मामले शामिल हैं। इसके अलावा, भारत सरकार के दिशानिर्देशों और राज्य वित्तायोग के अनुसार 15वें वित्तायोग के निर्धारित अनुदानों का उपयोग केवल पेयजल और स्वच्छता सेवाओं के लिये किया जाना है, जिन्हें 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा जाना है। यह ढांचा सुनिश्चित करता है कि ग्राम पंचायतें योजना और निगरानी में अहम भूमिका निभायें, पेयजल आपूर्ति योजनाओं को कियान्वयित करने और बनाये रखने में कई पंचायतों द्वारा सामना की जाने वाली तकनीकी और वित्तीय बाधाओं को देखते हुये सरकार ने निर्णय लिया है कि जल शक्ति विभाग ऐसी योजनाओं के लिये नामित सेवा प्रदाता/विक्रेता के रूप में कार्य करेगा। तदानुसार, ग्राम पंचायतों को जल शक्ति विभाग के फील्ड पदाधिकारियों के साथ गहन (Close) परामर्श करके सहायता की आवश्यकता वाली जल आपूर्ति योजनाओं की पहचान करनी है और उन्हें ग्राम सभाओं द्वारा विधिवत अनुमोदित अपनी जी0पी0डी0पी0 में शामिल करना है।

चूंकि पंचायतों के पास इन योजनाओं को कियान्वित/चलाने की तकनीकी क्षमता नहीं है, इसलिये जल शक्ति विभाग इन योजनाओं के लिये निष्पादन एजेंसी के रूप में काम करेगा और इसके फील्ड अधिकारी (Executive Engineers/SDOs) को ग्राम स्वराज पोर्टल पर सर्विस प्रोवाईडर्स/वेंडर्स के रूप में दर्शाया जायेगा। इससे पंचायतों को पेयजल घटक/मद के लिये 15वें वित्तायोग के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि को निर्धारित अनुदान में स्थानान्तरित करने में सहायता मिलेगी, जिसे जल शक्ति विभाग की फील्ड एजेंसियों को स्थानान्तरित किया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पंचायतों को इस उद्देश्य के लिये जल शक्ति विभाग को धनराशि स्थानान्तरित करने के लिये अधिकृत करने वाला एक औपचारिक प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। मार्गदर्शन के लिये सरकार द्वारा अनुमोदित उक्त प्रस्ताव का एक टैम्पलेट संलग्न है। इसके अलावा, सरकार ने योजनाओं को पूर्ण करने और रखरखाव के लिये पंचायतों के पास पड़े un-utilised tied grants को जल शक्ति विभाग को स्थानान्तरित करने की अनुमति दी है, जो उचित समाधान और प्रकियात्मक अनुपालन के अधीन है।

इस पहल के एक हिस्से के रूप में, वित्तीय स्थिरता और सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिये यूजर चार्जिज के संग्रह के लिये एक समान प्रणाली भी शुरू की गई है। वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने और

सामुदायिक स्वामित्व को मजबूत करने के लिये, यूजर चार्जिज एकत्र करने के लिये एक समान प्रणाली शुरू की जा रही है। सभी पंचायत प्रतिनिधि प्रति परिवार प्रति माह 100/–रू0 यूजर चार्जिज का भुगतान करेंगे और अन्य परिवार जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, वे ग्राम सभा द्वारा तय किये गये 50/–रू0 से 100/–रू0 प्रति माह तक मासिक शुल्क का योगदान देंगे, जबकि बी0पी0एल0 परिवार 25/–रू0 प्रति माह का एक निश्चित शुल्क देंगे। यह संरचित दृष्टिकोण (Structured approach) न केवल जल आपूर्ति प्रणाली के निरन्तर संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करेगा बल्कि पंचायतों के लिये राजस्व का एक आंतरिक स्त्रोत भी बनायेगा। यूजर चार्जिज की कलेक्शन पंचायत सचिव, चौकीदार, स्वयं सहायता समूह या ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से अधिकृत किसी अन्य एजेन्सी द्वारा किया जा सकता है और इसे समय पर **नामित योजना खाते** में जमा किया जायेगा। इन निधियों का उपयोग विकास कार्यों, स्वच्छता, ग्रामीण जलापूर्ति अवसंरचना के रखरखाव और ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिये किया जाना है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है और पंचायत व ग्राम सभा की कार्यवाही के रिकॉर्ड में पारदर्शी रूप से रिफ्लेक्ट होना चाहिये।

सरकार द्वारा स्वीकृत एक एस0ओ0पी0 इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। इसमें फण्ड ट्रांसफर के तौर–तरीके, वेंडर मैपिंग, जल शक्ति विभाग की सेवा वितरण बाध्यतायें, यूजर चार्जिज, कलेक्शन मेकेनिजम और शिकायत निवारण ढांचे का विवरण दिया गया है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप संलग्न एस0ओ0पी0 अनुसार निर्देशों का पूर्ण कार्यान्वयन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्त।

खण्ड विकास अधिकारी
विकास खण्ड सोलन

पृष्ठांकन संख्याः–यथोपरि। 967 to 1006 दिनांकः–

प्रतिलिपिः–1 सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज), हि0 प्र0 की सेवा में सूचनार्थ।

2 जिला विकास अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, सोलन, जिला सोलन, हि0 प्र0 की सेवा में सूचनार्थ।

3 समस्त प्रधान, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन, हि0 प्र0 को सूचनार्थ व निवेदन है कि आप संलग्न एस0ओ0पी0 का पूर्ण कार्यान्वयन करने की कृपा करें।

खण्ड विकास अधिकारी
विकास खण्ड सोलन

No. PCH-F(1)-1/2025
Government of Himachal Pradesh
Department of Rural Development & Panchayati Raj

To

1) The Addl. Chief Secretary (JSV) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2
2) All the Divisional Commissioners in the Himachal Pradesh
3) The Director, Panchayati Raj, Himachal Pradesh, Shimla-9
4) The Engineer-in-Chief, Jal Shakti Vibhag, Himachal Pradesh
5) All the Deputy Commissioners in the Himachal Pradesh
6) All the District Panchayat Officer in the Himachal Pradesh
7) All Executive Engineers / Sub-Divisional Officers, Jal Shakti Vibhag in Himachal Pradesh
8) All Block Development Officers in the Himachal Pradesh
9) All Gram Panchayats (through respective BDOs)

Block Development Officer Diary No. 519 Date 17-5-25

Dated: Shimla-171002, the 15 May, 2025

Subject: **Implementation of Cabinet Decisions on Transfer of 15th Finance Commission Tied Grants for Drinking Water Supply Schemes and Collection of User Charges – Issuance of Operational Instructions and SoP**

Sir/Madam,

I am directed to invite your attention to the subject cited above and to convey that, under the 15th Finance Commission, tied grants have been earmarked for Gram Panchayats to strengthen drinking water and sanitation services in rural areas. The Section 11 of the Himachal Pradesh Panchayat Raj Act, 1994, outlines the functions of the Gram Panchayat. Specifically, it states that the Gram Panchayat shall perform the functions specified in Schedule-I of the Act amongst other functions responsibilities of the Gram Panchayat, which include matters related to sanitation, conservancy, and the prevention of nuisances. Further, as per Government of India guidelines and State Finance Commission, 15th Finance Commission tied grants are to be utilised exclusively for drinking water and sanitation services, which are to be entrusted to Panchayati Raj Institutions as per the 73rd Constitutional Amendment. This framework ensures that Gram Panchayats play a central role in planning and oversight, while technical execution may be supported through line departments like the Jal Shakti Vibhag for effective service delivery. Recognising the technical and financial constraints faced by many Panchayats in executing and maintaining drinking water supply schemes, the Government has decided that the Jal Shakti Vibhag (JSV) shall act as the designated *Service Provider/Vendors* for such schemes. Accordingly, Gram Panchayats are to identify the water supply schemes requiring support in close consultation with the field functionaries of JSV and incorporate them in their Gram Panchayat Development Plans (GPDPs), duly approved by the Gram Sabhas.

2. As Panchayats do not have technical capability to execute/run these schemes, the JSV Shall serve as the executing agency for these schemes, and its field officers (Executive Engineers/SDOs) will be mapped as Service Providers/vendors on the Gram Swaraj portal. This will enable Panchayats to transfer funds available under 15th Finance Commission for Drinking Water Component in the tied grant which shall be transferred to JSV field agencies. It is also clarified that Panchayats are required to pass a formal resolution authorizing the transfer of funds to JSV for this purpose. A template for the said resolution, approved by the Government, is enclosed for guidance. Furthermore, the Government has allowed the transfer of un-utilised tied grants lying with Panchayats to JSV for completion and maintenance of schemes, subject to due resolution and procedural compliance.

3. As part of this initiative, a uniform system for collection of user charges has also been introduced to promote financial sustainability and community ownership. To promote financial sustainability and strengthen community ownership, a uniform system for collecting user charges is being introduced. All the PRI representatives will pay user charges @ Rs.100 per household per month and households those other families which are above the poverty line will contribute a monthly charge, ranging from Rs. 50 to Rs.100 per month, as decided by the Gram Sabha, while BPL households will pay a fixed charge of 25 per month. This structured approach will not only ensure the continued operation and maintenance of water supply systems but will also create an additional source of revenue for the Panchayats. The collection may be undertaken by the Panchayat Secretary, Chowkidar, Self Help Group (SHG), or any other agency as authorised by the Gram Panchayat through resolution, and must be deposited into the designated scheme account in a timely manner. These funds are to be used for the developmental works; sanitations, upkeep of rural water supply infrastructure & such other purposes as may be specified from time to time by the State Government and must be transparently reflected in the records of the Panchayat and Gram Sabha proceedings.

4. A Standard Operating Procedure (SoP) approved by the Government is being annexed with this communication. It details the fund transfer modalities, vendor mapping, service delivery obligations of JSV, user charge

collection mechanism, and grievance redressal framework. All concerned are requested to familiarise themselves with the SoP and ensure its thorough implementation.

Yours faithfully,

(Rajesh Sharma), IAS
Secretary (Rural Dev.& PR) to the
Government of Himachal Pradesh

Standard Operating Procedure (SoP) for Transfer of 15th Finance Commission Tied Grants to Jal Shakti Vibhag (JSV) and Collection of User Charges by Gram Panchayats

1. **Background**

As per Section 11 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, Gram Panchayats are mandated to perform various civic and developmental functions, including the provision and maintenance of adequate drinking water supply within their jurisdiction. This statutory responsibility underlines the critical role of Panchayats in ensuring access to safe and reliable water for rural communities.

The 15thFinance Commission has earmarked tied grants to Gram Panchayats for the provision of drinking water and sanitation services. In view of the technical and financial limitations faced by Gram Panchayats in executing and maintaining drinking water supply schemes, it has been decided that the Jal Shakti Vibhag (JSV) shall serve as the executing agency for such schemes. This SoP outlines the process of fund transfer, execution responsibilities, user charge collection, and utilisation protocols to ensure effective service delivery and compliance with the Finance Commission's guidelines.

This Standard Operating Procedure is being issued in view of the persistent underutilisation of 15th Finance Commission tied grants by Gram Panchayats, in the drinking water component. Despite the availability of funds, a substantial portion remains unutilised due to the inability of Panchayats to construct new water supply schemes within the limited financial allocation and in the absence of technical support. Many Panchayats also face difficulties due to scarcity of sustainable water sources and lack of engineering capacity. The Manual for Utilisation of 15thFinance Commission Grants issued by the Government of India envisages convergence with line departments and alternative delivery mechanisms to optimise outcomes. In this context, these SoP are intended to ensure that available funds are channelled effectively through a technically competent agency while preserving the decentralised mandate of Gram Panchayats, thereby improving rural service delivery and enhancing compliance with the Government of India's devolution norms.

2. **Identification and Planning of Schemes**

a) Gram Sabha shall identify water supply schemes requiring support and discuss these with local officers of JSV.

b) Schemes shall be incorporated into the Gram Panchayat Development Plan (GPDP) with approval from the Gram Sabha, in the following manner: -

Secretary (RD & PR)

(English version)

"The Gram Panchayat resolves to transfer funds for the operation and maintenance of drinking water supply schemes to the XEN or AE of Jal Shakti Vibhag as a service provider/ vendor, ensuring effective execution and utilisation of the 15th Finance Commission Tied Grant. The schemes identified for execution shall be included in the supplementary GPDP plan after due approval in the Gram Sabha."

(हिंदी संस्करण)

"ग्राम पंचायत यह प्रस्ताव पारित करती है कि पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रख रखाव हेतु 15वें वित्तआयोग के आबद्ध अनुदान का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति विभाग द्वारा चिन्हित अधिशाषी अभियंता या सहायक अभियंता को सेवा प्रदाता/विक्रेता के रूप में निधि हस्तांतरित की जाएगी। कार्यान्वयन हेतु चिन्हित योजनाओं को ग्राम सभा की स्वीकृति के पश्चात अनुपूरक जी०पी०डी०पी योजना में सम्मिलित किया जाएगा।"

3. Fund Transfer and "Service Provider" Mapping

a) Field officers of JSV (e.g., Executive Engineers or SDOs) shall be mapped as 'Service Provider/Vendor' in the Gram Swaraj portal.

b) Upon approval of the GPDP, Panchayats shall pass resolutions authorising fund transfer to JSV.

c) Funds shall be transferred directly from Panchayat accounts to JSV through the GramSwaraj platform.

4. Execution and Service Delivery by JSV

a) JSV shall ensure regular and uninterrupted water supply to all covered households.

b) JSV shall through the funds collected as above, undertake necessary repairs of water supply schemes, pay electricity bills, and manage daily operations.

c) JSV shall submit monthly progress reports and quarterly utilisation certificates to the Panchayats and the Block Development Officer.

d) JSV shall notify the Panchayat of any planned disruptions or maintenance schedules in advance.

5. User Charge Collection

a) All the PRI representatives will pay user charges @ ₹100 per household per month and households above the poverty line will contribute a monthly charge, ranging from ₹50 to ₹100 per month, as decided by the

Secretary (RD & PR)

Gram Sabha, while BPL households will pay a fixed charge of ₹25 per month.

b) The Gram Panchayat shall authorise a local agent (Secretary, Chowkidar, SHG etc.) for monthly collection.

c) Collected charges shall be deposited in the designated Panchayat account linked with the scheme.

d) Failure to pay charges for three consecutive months shall lead to disconnection of supply by JSV, and fines may be imposed by the Panchayat under the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act.

6. Utilisation of Funds

a) User charges shall be used exclusively for various infrastructure & sanitation and such other purposes as may be specified form time to time by State Govt. at Gram Panchayat Level after having the approval of the Gram Sabha.

b) Expenditures must be reflected in the Panchayat's accounts and presented in the Gram Sabha.

c) Any surplus shall be carried forward for future use or enhancement of services.

7. Monitoring and Accountability

a) Block Development Officers shall monitor implementation and take suitable necessary action for implementation of the SoP.

b) A grievance redressal mechanism shall be maintained by JSV at the Block/Sub-Division level.

c) Annual joint reviews of JSV's performance shall be undertaken with the Panchayats.

8. Transparency Measures

a) Panchayats shall publicly display supply schedules and contact details of the JSV officer responsible.

b) Quarterly reports and financial statements shall be made available for public scrutiny.

(Rajesh Sharma), IAS
Secretary (Rural Dev. & PR) to the
Government of Himachal Pradesh